भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 692

07 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए नियत

'फेम' योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसें

692. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:
श्री सत्यदेव पचौरी:
श्री गौरव गोगोई:
श्री रामोहन नायडू किंजरापु:
श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण की स्कीम फेम इंडिया के प्रथम और द्वितीय चरण के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित इलेक्ट्रिक बसों की आवश्यकता से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या फेम-।। योजना के तहत देश के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें सड़कों/मार्गों पर आनी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फेम इंडिया चरण-। और ।। के तहत स्वीकृत इलेक्ट्रिक बसों की तुलना में परिचालित बसों की कुल संख्या की संपरीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार प्रदूषणमुक्त सार्वजनिक परिवहन के लिए और अधिक इलेक्ट्रिक वाहन स्वीकृत करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (घ): महोदय, भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक बसों सहित इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीगरण को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम तैयार की। वर्तमान में,

फेम इंडिया स्कीम का दूसरा चरण कुल 10,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय से दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस स्कीम के तहत, स्कीम के पहले चरण में दी गई स्वीकृति के अनुसार, 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें लगभग 280 करोड़ रुपये के सरकारी प्रोत्साहन के साथ देश के विभिन्न शहरों में तैनात की गई हैं।

फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण में, भारी उद्योग मंत्रालय ने अंतर-नगरीय प्रचालन हेतु 65 शहरों/एसटीयू/राज्य सरकार संस्थाओं के लिये 6315 ई-बसों की स्वीकृति दी जिसमें, 650 ई-बसों को अंतर-नगरीय प्रचालनों के लिए अनुमोदित किया गया था और अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के लिए 100 ई-बसों को स्वीकृति दी गई थी। इन 6315 ई-बसों में से, नगर के भीतर और अंतर-नगरीय प्रचालनों तथा अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए लगभग 3738 इलेक्ट्रिक बसों के आपूर्ति आदेश जारी किए गए हैं। इन 3738 ई-बसों में से, 2232 इलेक्ट्रिक बसों को परिनियोजित किया जा चुका है; 340 बसों को मुंबई शहर में तैनात किया गया है, नवी-मुंबई में 150 बसों, अहमदाबाद में 150 बसों, पुणे में 150 बसों, उत्तर प्रदेश में 521 बसों, बीएमटीसी में 150 बसों, गोवा में 50 बसों, पटना में 25 बसों, सूरत में 104 बसों, राजकोट में 47 बसों, डीएमआरसी में 59 बसों, चंडीगढ़ में 80 बसों, डीटीसी में 250 बसों, सिल्वासा में 25 बसों, देहरादून में 30 बसों, ओडिशा में 10 बसों, जीएसआरटीसी में 50 बसों, कोलकता में 7 बसों, एपीएसआरटीसी में 10 बसों, एमएसआरटीसी में 2 बसों और नागपुर में 22 बसों को तैनात किया गया है।

(ङ.) और (च): फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण में मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझाकृत परिवहन के विद्युतीकरण के लिए समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसका उद्देश्य मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई- चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है।

***